सुधारों का पिटारा खोलेगा आम बजट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार विकास की पटरी पर वापस लाने के इरादे से घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने लिए सरकार आम बजट में सुधारों का पिटारा खोलेगी। वित्त मंत्री 28 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए 'दूसरी पीढ़ी' के आर्थिक सुधारों का एलान कर सकते हैं। इसमें लंबित आर्थिक सुधारों के साथ व्यय सुधारों के रूप में कई ऐसे उपाय भी होंगे, जिनसे आम लोगों खासकर गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि आम बजट 2015-16 में सरकार दूसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा करेगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ढांचागत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुधारात्मक कदम उठा सकती है। सूत्रों का कहना है कि आम बजट में कर, व्यय और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार सुधारों (जैसे बैंकिंग क्षेत्र के सुधार) की घोषणा की जा सकती है। साथ ही बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का एक रोडमैप भी घोषित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय गार (जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स) को लागू करने की नई समय सीमा का एलान भी कर सकता है। गार को पहले एक अप्रैल, 2014 से लागू किए जाने की योजना थी। निवेशकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने इसे 2016 तक टाल दिया। अब भी निवेशक इसे लेकर आशंकित हैं। इसलिए राजग सरकार इसे और आगे खिसका सकती है। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डीटीसी के भविष्य को लेकर भी वित्त मंत्री स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। वित्त मंत्री आम बजट में बैंकिंग सुधारों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों के लिए रोडमैप जारी कर सकते हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है। एक विचार यह भी है कि कुछ बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत की जाए। हालांकि बैंकिंग यूनियनों के विरोध के मद्देनजर इसके आसार कम ही हैं। वित्त मंत्री सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए भी उपायों की घोषणा करेंगे।

वित्त मंत्री की नजर

- खाद्य और खाद सब्सिडी का बोझ कम करना
- मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को तर्कसंगत बनाना
- पूंजीगत खर्च को बढ़ाना, बैंकिंग सुधारों का खाका पेश करना
- वस्तु एवं सेवा कर के लिए रोडमैप घोषित करना

लचर प्रदर्शन वाले बैंकों पर मेहरबानी नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार की चेतावनी और तमाम कोशिशों के बावजूद वित्तीय स्थिति सुधारने में असफल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली खास मेहरबानी दिखाने के मूड में नहीं है। जेटली फंड की कमी वाले बैंकों के लिए खजाना खोलेंगे, लेकिन इसका ज्यादा लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिन्होंने पिछली तिमाहियों में अपने एनपीए (फंसे कर्जे) की स्थिति सुधारी है और मुनाफा बढ़ाने के उपाय किए हैं।

अगले वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी बैंकों की पूंजी जरूरत पूरी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा हो सकती है। वैसे बेसिल-3 मानकों के तहत 2,40,000 करोड़ रुपये की जरूरत को देखते हुए यह रकम काफी कम है। पिछले पांच वित्त वर्षों से हर साल सरकारी बैंकों को 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की राशि बजट से दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 11,200 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया था। इसमें से राजग सरकार ने सिर्फ नौ बैंकों को 6,990 करोड़ रुपये अभी तक दिए हैं। सिर्फ उन्हीं बैंकों को इसका फायदा दिया गया जिन्होंने सरकार के मानकों के मुताबिक प्रदर्शन किया है। यही फार्मूला आगे भी जारी रहेगा।जानकारों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार की बैंकिंग नीति कैसी रहेगी। लेकिन इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उसके रोडमैप की बानगी वित्त मंत्री आम बजट में पेश कर सकते हैं। सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी समस्या फंसे कर्जे की है, लेकिन वित्त मंत्री के पास इससे पार लगाने का कोई अस्त्र नहीं है। हां, बैंकों को बकाया कर्ज वापसी के लिए वह कुछ नए हथियार दे सकते हैं। मसलन, प्रतिभूति कानून में एक और संशोधन किया जा सकता है।

बैंकों की जमा राशि की बेहद धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ नई सावधि जमा (एफडी) स्कीमों का एलान होने की भी संभावना है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से नए किस्म के ऋण उत्पादों पर सुझाव भी मांगे थे। इसके अलावा बेहद सफल जन धन योजना के तहत अन्य वित्तीय उत्पादों को आम जनता को देने के संबंध में भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

जेटली का इरादा

- एनपीए व फंड की कमी से जूझते बैंकों के लिए घोषणा संभव
- 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी अगले वित्त वर्ष में देने की योजना
- लेकिन वित्तीय स्थिति सुधारने वाले बैंकों को ही मिलेगा फायदा
- जन धन के तहत शुरू होगा वित्तीय समावेश का दूसरा चरण

वित्त मंत्री ने की हड़ताल पर न जाने की अपील

जाब्यू, नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे अपनी चार दिन की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लें। जेटली ने कहा कि हड़ताल में शामिल होने की न तो कोई जरूरत है और न ही यह देश के हित में है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 25 फरवरी से चार दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसी दौरान 28 फरवरी को बजट पेश होना है। इसे देखते हुए जेटली ने बैंकों के कर्मियों से यह अपील की है कि वे व्यवधानकारी तरीके न अपनाएं और हड़ताल पर न जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की मांगों के संबंध में उनकी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसलिए बैंक कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं अपनाना चाहिए।

सरकारी बैंकों का सूरतेहाल

1. फंसे कर्जे यानी एनपीए की स्थिति बेहद खराब
2. पिछली तिमाही में 24,000 करोड़ की कर्ज राशि का पुनर्गठन
3. कर्मचारी संगठनों में निराशा, लगातार हड़ताल की धमकी
4. जन धन से जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन वित्तीय तौर पर लाभ नहीं
5. बेसिल-3 के तहत 2.40 लाख करोड़ रुपये जुटाना बड़ी चुनौती
6. तकनीकी इस्तेमाल को लेकर सरकारी बैंक अभी काफी पीछे
7. कई बड़े बैंकों के प्रमुख का पद अब तक नहीं भर पाई सरकार

स्वास्थ्य का हाल

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहने की बात हम सबको पता है लेकिन शायद सरकार इससे जानबूझकर अनजान बने रहना चाहती है। तभी तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करती है। देश को स्वस्थ रखने के लिए कुल जीडीपी का महज 0.29 फीसद धन आवंटित करती है जिसे पूरा खर्च भी नहीं कर पाती है। इससे आप स्वास्थ्य क्षेत्र के हाल का अंदाज लगा सकते हैं।

₹1,69,408 करोड़ भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2007 से मार्च 2013 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम आवंटित कुल धन

0.29% देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कुल आवंटन की हिस्सेदारी (2012-13)

वह धन जो खर्च नहीं हुआ 31% ₹51,947 करोड़

69% कुल आवंटित धन का हिस्सा

कुल खर्च धन ₹1,17,461 करोड़

79%	₹84,174 करोड़
54%	₹24,367 करोड़
35%	₹2,621 करोड़
50%	₹2,590 करोड़
76%	₹3,709 करोड़

परत दर परत

धन का वितरण

63%	₹1,06,575 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
27%	₹45,275 करोड़ स्वास्थ्य विभाग (अन्य कार्यक्रम)
04%	₹7,488 करोड़ एड्स नियंत्रण विभाग
03%	₹5,221 करोड़ स्वास्थ्य शोध विभाग
03%	₹4,849 करोड़ आयुष विभाग

एनआरएचएम के तहत खर्च न किया गया धन

उत्तर प्रदेश	₹819 करोड़
राजस्थान	₹300
ओडिशा	₹141
तमिलनाडु	₹141
मध्य प्रदेश	₹140
कर्नाटक	₹105
छत्तीसगढ़	₹102
महाराष्ट्र	₹100
पंजाब	₹52
पश्चिम बंगाल	₹28
झारखंड	₹23

स्रोत: अकाउंटबिलिटी इनीशिएटिव, सीपीआर

एक नजर

विदेशी मुद्रा भंडार 333 अरब डॉलर

मुंबई: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 333.17 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पूर्व के सप्ताह के मुकाबले इसमें 2.95 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा संपत्तियों में वृद्धि के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई। मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार से देश अपने 10 माह के आयात का खर्च उठा सकता है।

बाल्को को मिली एक और खदान

नई दिल्ली: कोयला नीलामी के आठवें दिन भारत अल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) ने एक और कोयला खदान झटक ली। छत्तीसगढ़ में स्थिल गारे पाल्मा खान के लिए इस कंपनी ने 1,585 रुपये प्रति टन की बोली लगाई है। बाल्को इसी राज्य की छोटिया खदान पहले ही नीलामी में हासिल कर चुकी है।

गुड़गांव में अर्थ स्काई गेट परियोजना

नई दिल्ली: अर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एएमबी ग्रुप के साथ मिलकर गुड़गांव में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना अर्थ स्काई गेट की शुरुआत की है। न्यू गुड़गांव के दूसरे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के मुकाबले यह अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। कंपनी का यह प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है।

जीना मुश्किल कर दे प्रताड़ना

लंदन: दफ्तर में प्रताड़ना का हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभाव पीड़ित के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह पीड़ित को व्यग्र करता है, उसका उत्साह घटाता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और भविष्य में बार-बार प्रताड़ित किए जाने की उसके अंदर आशंका भी बढ़ जाती है। एक नए अध्ययन से यह बात सामने आई है। ईस्ट एंजिला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्रताड़ना के इस 'सर्पिल' दुष्चक्र की व्याख्या की है। नॉर्विक बिजनेस स्कूल की डॉ. अना सांज वर्गेल ने बताया कि तंग करना, धमकी देना और सार्वजनिक तौर पर नौकरी छोड़ने के लिए बार-बार कहना प्रताड़ना के कुछ उदाहरण हैं। कॉम्पल्यूटेंस यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड के शोधकर्ता भी अध्ययन में शामिल थे। 348 स्पेनिश कर्मचारियों पर यह अध्ययन किया गया।

पूर्व कैग विनोद राय के आरोपों पर बिफरे पटेल

पणजी, प्रेट्र: राकांपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अपने कार्यकाल में सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की दुर्दशा पर पूर्व कैग विनोद राय द्वारा सवाल उठाए जाने पर खासा नाराज हो गए। इसे बेकार की बातें करार देते हुए पटेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में जो भी विवाद हुआ था, वह कब का समाप्त और दफन हो चुका है।

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय ने अपनी किताब 'नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट : द डायरी ऑफ द नेशंस कॉनशंस-कीपर' में आरोप लगाया है कि 2004 में एयर इंडिया द्वारा नए विमानों की संख्या 28 से बढ़ाकर 68 करने के लिए पटेल जिम्मेदार थे। पटेल के इस फैसले की बाद में काफी आलोचना भी हुई थी। राय के आरोपों पर राकांपा नेता पटेल ने शनिवार को यहां कहा, 'हम क्यों बेकार की बातों पर बहस कर रहे हैं। जो लोग इसको सनसनीखेज बनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं अब इसका कोई महत्व है। यह मामला बहुत पहले ही समाप्त और दफन हो चुका है।'

पटेल ने कहा कि राय की किताब पढ़ ही कौन रहा है? उनकी किताब भी दफन हो चुकी है। भाजपा की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति ने राय के रुख का नहीं बल्कि विमानों की संख्या बढ़ाए जाने के उनके फैसले का समर्थन किया था। पटेल ने कहा कि राय को यह सब बाते अपनी किताब में नहीं बल्कि कैग की रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए था।

- कहा, राय की किताब को पढ़ ही कौन रहा है, वह किताब भी हो चुकी है दफन

कमीशन के 275 करोड़ लौटाए एसबीआइ लाइफ

चेन्नई, आइएएनएस : इरडा ने कहा है कि एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस को बीमा ग्राहकों के 275 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। इस बीमा कंपनी ने ग्राहकों से ज्यादा कमीशन के तौर पर यह राशि वसूली थी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन टीएस विजयन ने फिर दोहराया है कि बीमा कानून के तहत उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा आदेश देने का अधिकार है। एसबीआइ लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ के बीच 74 व 26 फीसद की हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। विजयन ने एसबीआइ लाइफ को लिखे एक पत्र में निर्देश दिया है कि कंपनी उसके मार्च, 2014 के कमीशन लौटाने के आदेश का पालन करे। यह पत्र इरडा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सेवा क्षेत्र की बाधाएं हटाकर बढ़ानी होगी गति

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोदी सरकार सेवा क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए खास सुधारों को आगे बढ़ाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने सेवा निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सेवा क्षेत्र से जुडे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि निर्मला ने सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने उन तमाम सेवाओं के सामने आने वाली अड़चनों की पहचान करने के बाद विशिष्ट सुधारों की पहल करनी की भी बात कही। सीतारमण के मुताबिक, बेहतर सेवाओं से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत में कमी आएगी। इससे मैन्यूफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ जाएगी। मेक इन इंडिया अभियान की सफलता में सेवाओं की प्रमुख भूमिका होगी। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सेवा क्षेत्र ने बड़ी भूमिका निभाई है। मंत्री ने सवाल भी किया कि जब देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 57 प्रतिशत योगदान है तो फिर विश्व सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 3.24 प्रतिशत के निचले स्तर पर क्यों बनी हुई है? बैठक में संसद की सलाहकार समिति को सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा सेवा क्षेत्र के लिए अंतर मंत्रालयी समूह और अलग-अलग सेवाओं की खातिर उपसमूह बनाए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय हर साल सेवा क्षेत्र पर सम्मेलन का आयोजन करता है। वाणिज्य मंत्रालय यहां सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग चैंबर सीआइआइ के सहयोग से 23 से 25 अप्रैल के बीच वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस) का आयोजन करने जा रहा है।

बोलीं सीतारमण

- मेक इन इंडिया की सफलता में होगी सेवाओं की प्रमुख भूमिका
- बेहतर सेवाओं से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत में आएगी कमी

जारी रहेगी मतंग सिंह की जेड प्लस सुरक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित लोकसभा की स्पीकर रहीं मीरा कुमार की सुरक्षा पूर्ण रूप से वापस ले ली है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सारधा घोटाले के आरोपी मतंग सिंह की जेड प्लस सुरक्षा को बरकरार रखा है। जेल में बंद सिंह को पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा 14 सूबों में यह सुरक्षा घेरा मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में गृह सचिव एलसी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।

कांग्रेसी दिग्गजों की सुरक्षा वापस : लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, श्रीप्रकाश जायसवाल, रीता बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद, पीएल पुनिया और सलीम शेरवानी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा और आरपीएन सिंह की सुरक्षा को जेड प्लस से घटाकर वाई श्रेणी में कर दिया गया है। वाई श्रेणी में चार सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। अमर सिंह भी जेड प्लस से वाई श्रेणी की सुरक्षा में आ गए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिन्हा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह सचिव गोयल की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में एनएसजी कमांडों के घेरे में रहने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था सीमित करने पर भी सहमति बनी। इस बारे में आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है।

- कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों समेत मीरा कुमार की सुरक्षा वापस
- गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला

चांदी और लुढ़की, सोना भी फिसला

नई दिल्ली/लखनऊ, प्रेट्र/जाका : औद्योगिक यूनिटों और सिक्का निर्माताओं की मांग कमजोर बनी रहने से चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। स्थानीय सराफा बाजार में शनिवार को सफेद धातु 315 रुपये लुढ़ककर 36 हजार 885 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। बीते सत्र में भी यह 200 रुपये फिसली थी। इसी तरह सोना 10 रुपये टूटकर 27 हजार 190 रुपये रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। यह पीली धातु शुक्रवार को भी 85 रुपये कमजोर हुई थी।

सोना आभूषण के भाव 10 रुपये घटकर 26 हजार 990 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुए। आठ ग्राम वाली गिन्नी पूर्वस्तर 23 हजार 700 रुपये पर यथावत रही। चांदी साप्ताहिक डिलीवरी 300 रुपये गंवाकर 36 हजार 265 रुपये प्रति किलो बोली गई। इसी प्रकार चांदी सिक्का 1000 रुपये लुढ़ककर 59000-60000 रुपये प्रति सैकड़ा पर आ गया। वहीं, लखनऊ में सोना और चांदी के दाम एक दिन पहले के स्तर पर यथावत रहे। सोना 27 हजार 150 रुपये पर जबकि चांदी 37 हजार 300 रुपये पर बंद हुई।

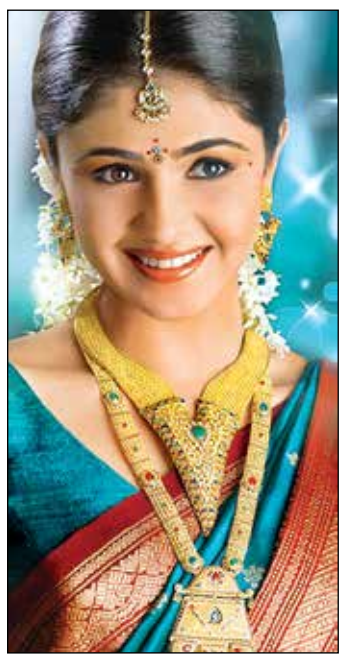

एसिड हमले पर तय समय में फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशभर में एसिड हमले की बढ़ती घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार ने अब इसकी जांच और कोर्ट में फैसले के लिए समय सीमा तय करने का फैसला किया है। साथ ही हमले के दोषियों को अधिकतम सजा सुनिश्चित की जाएगी। देश में हर माह एसिड हमलों के लगभग चार सौ मामले दर्ज किए जाते हैं। 'एसिड पीड़ितों का सशक्तीकरण' विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि उनका मंत्रालय इसके लिए सीआरपीसी में जरूरी संशोधन की तैयारी कर रहा है। राजनाथ ने कहा, 'मैं पहले ही राज्य सरकारों को इस संबंध में लिख चुका हूं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग इस तरह के अपराध में शामिल हैं, उन्हें अधिकतम सजा दिलाई जा सके।' उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह का प्रावधान करने जा रही है, जिससे एसिड हमला सहित अन्य जघन्य अपराधों में समय सीमा के अंदर अदालतों से फैसला आ जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि एसिड की बिक्री को विनियमित करने, हमलावरों की सजा बढ़ाने और पीड़ितों को मुआवजा देने सहित कई कदम सरकार पहले ही उठा चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए कानून बना चुके हैं।

सीआरपीसी में संशोधन

- निश्चित समय में जांच,सुनिश्चित की जाएगी अधिकतम सजा

आजीवन कारावास तक की सजा

फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम-2013 के अनुसार एसिड हमले के दोषियों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि जिन मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है, उन्हें जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाएगा।

विश्व के सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं : स्वामी

नई दुनिया, इंदौर : भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर व्याख्यान देने इंदौर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डीएनए टेस्ट के अध्ययन में यह बात साबित हो चुकी है कि विश्व के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण पर उन्होंने कहा राम मंदिर तो अयोध्या में बनकर ही रहेगा। समस्या सिर्फ यह है मस्जिद को कहां स्थान दिया जाए।

इस संबंध में सऊदी अरब के मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा हो चुकी है। मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है। वह तो सिर्फ इबादत का स्थान है। सऊदी अरब व अन्य मुस्लिम देश अपनी सुविधा के हिसाब से मस्जिदों का स्थान बदल देते हैं। स्वामी ने कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बनकर रहेगा। मथुरा व काशी में भी मंदिर निर्माण होगा। आतंकी संगठन आइएसआइएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह हिंदुस्तान को इस्लाम का अधूरा इतिहास कहता है। इसका कारण यह है कि जहां भी इस्लाम गया है, वहां 100 फीसदी जनसंख्या को मुसलमान बना दिया गया। इरान, इराक, इजिप्ट और यूरोप के कई देश इसके उदाहरण हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमानों और 200 साल इसाइयों का राज होने के बावजूद आज भी देश की 80 फीसद जनता हिंदू है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर स्वामी ने कहा कि भाजपा तो सिर्फ हारी है, लेकिन कांग्रेस ने तो आत्महत्या ही कर ली है। कांग्रेस में अब प्रियंका भी जान नहीं डाल सकतीं। राहुल गांधी को लंदन की पार्टी से ही फुर्सत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्वामी ने 420 करार दिया। कहा कि केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं। उनके सिद्धांत नक्सलाइट हैं। व्यापमं घोटाले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। इससे कुछ नहीं होता। जांच हो जाने दो सच्चाई सामने आ जाएगी। जबकि सुनंदा हत्याकांड की जांच धीमी गति से चल रही है। शशि थरूर को सीधे जेल में डाल देना चाहिए।

- भाजपा नेता ने कहा, अयोध्या में ही बनेगा मंदिर

मंगलवार तक अतिविशिष्ट पर दर्ज हो सकती है एफआइआर

नई दुनिया ब्यूरो, भोपाल : एसआइटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस चंद्रेश भूषण ने फिर मीडिया से कहा कि अतिविशिष्ट लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के पहले कानूनी पहलुओं पर विचार करना पड़ रहा है। लेकिन इनके खिलाफ मंगलवार तक एफआइआर दर्ज हो सकती है। इस सिलसिले में सोमवार को एसआइटी की बैठक होगी।

जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए उनके ओहदे के हिसाब से कानून होता है। चर्चा के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्ति के नाम के मामले में वे कुछ भी कहने से बचते रहे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से एसटीएफ के अधिकारियों पर लगाए गए डाटा डिलीट करने के सवाल पर जस्टिस भूषण का कहना था कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। यदि इसमें सच्चाई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एसआइटी पूरी बारीकी से जांच की मॉनीटरिंग कर रही है। इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल रामनरेश यादव पर धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किए जाने और उनके बेटे शैलेष को मुख्य आरोपियों में शामिल किए जाने की सिफारिश एसआइटी ने हाई कोर्ट से की थी, जिसे अदालत ने सहमति दे दी है।